मुख्यमंत्री भजन लाल ने शहरी सेवा शिविर के लिए निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि इन शिविरों में नागरिकों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर समाधान किया जायेगा

जयपुर, 11 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आमजन तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी सेवा शिविर का आयोजन करने जा रही है। 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही शिविर में जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर-कस्बे में इसका व्यापक असर दिखाई दे, इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और उनसे जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में विभाग द्वारा समग्र जानकारी की मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए।

उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर और मैनहोल की मरम्मत की जाएगी एवं प्रमुख चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों और सार्वजनिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण होगा।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर चलने वाले इस अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें।

- **शिविर से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था, सुनिश्चित करें तथा नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर व मैन होल की मरम्मत करायें।**

उल्लेखनीय है कि पहले 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन अब इस अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है, जिसके तहत अब यह शिविर15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

'खुले बाजार में पदों की नीलामी हो रही है'

हैदराबाद, 11 सितंबर। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ग्रुप-एक के पदों को बेचकर तेलंगाना के बेरोजगार युवाओं को धोखा दे रही है।

राव ने गुरुवार के अपने बयान में कथित घोटाले के लिए एक न्यायिक जांच और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। राव ने रिपोर्टों

- **बीआरएस के अध्यक्ष, के.टी. रामाराव ने तेलंगाना सरकार पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया।**

और छात्रों के आरोपों को लेकर चिंता व्यक्ति की, जिनमें कहा गया है कि नौकरियों के लिए भारी मात्रा में धन की मांग की गई थी और दावा किया कि सरकार ने ''खुले बाजार में पदों की नीलामी की।''

उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थी, जिन्होंने अपने सालों की मेहनत और संसाधन लगाये हैं, को अपनी उम्मीदें कुचली नजर आ रही हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए राव ने मांग की कि ग्रुप-एक प्रारंभिक परीक्षा बिना अनियमितता के दोबारा करायी जाये।

सीआरपीएफ का आरोप, सुरक्षा प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे राहुल

कांग्रेस ने सीआरपीएफ की रिपोर्ट को राहुल का आंदोलन रोकने की कोशिश करार दिया

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं लेकिन इसकी सूचना नहीं दी जाती है जो सरासर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस संबंध में सीआरपीएफ की तरफ से पत्र लिखकर कहा गया है कि गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं और बिना सूचना दिये विदेश यात्रा कर रहे हैं। सुरक्षा बल ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे परेशान होकर यह पत्र लिखना पड़ रहा है।

सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने खड़गे को बुधवार को लिखे पत्र में लिखा है कि गांधी अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

गांधी की इस साल की विदेश यात्राओं का विस्तारपूर्वक जिक्र करते हुए जून ने कहा है कि पिछले नौ माह में

- **सीआरपीएफ ने कहा, राहुल विदेश यात्रा की जानकारी भी नहीं देते हैं और भीड़ से मिलते हैं।**
- **कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा यह राहुल को डराने की कोशिश है असल में सरकार राहुल की वोट चोरी विरोधी मुहिम से डर गई है।**

गांधी छह बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। पत्र में बताया गया है कि गांधी 30 दिसंबर 2024 से नौ जनवरी 2025 तक इटली की यात्रा पर गये थे। फिर 12 से 17 मार्च तक वियतनाम, 17 से 23 अप्रैल तक दुबई, 11 से 18 जून तक कतर, 25 जून से छह जुलाई तक लंदन और हाल ही में चार दिन के लिए मलेशिया की यात्रा पर गये थे।

सीआरपीएफ द्वारा पत्र को सार्वजनिक करने और इसकी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे गांधी को डराने की कोशिश करार दिया है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गुरुवार को पत्र का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ के पत्र भेजने का समय और उसे तुरंत सार्वजनिक करने की मंशा परेशान करने वाली है। उनका कहना है कि गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर लिखे पत्र और उसे सार्वजनिक करने का समय सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा, """"यह पत्र ऐसे समय में आया है जब गांधी चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा द्वारा की जा रही वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। क्या यह विपक्ष के नेता को डराने की एक छिपी हुई कोशिश है, जिन्होंने पहले ही एक और खुलासे की घोषणा कर दी है। क्या सरकार उनके द्वारा उजागर किये जाने वाले सच से घबरा गयी है।""""

गौरतलब है कि गांधी को ज़ैड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है जो गंभीर खतरे की आशंका वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री ने सेवा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन कार्यक्रम के दौरान उस समय अचानक माहौल गर्मा गया, जब प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल कार्यशाला के पहले सत्र के बाद नाराज़गी के भाव में बिना मंच साझा किए ही निकल गए।

सूत्रों के अनुसार, कार्यशाला में कम उपस्थिति को लेकर प्रभारी नाखुश थे। उन्होंने मंच से ही कहा कि ''जो पार्टी का काम नहीं करना चाहता, उसे पार्टी में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए।'' उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से बिना बताए अनुपस्थित रहे सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से लिखित जवाब मांगने की बात कही। कार्यशाला में केवल 5 सांसद, 72 विधायक, 42 प्रत्याशी और 13 जिलाध्यक्ष ही पहुंचे थे, जिस पर अग्रवाल ने नाराज़गी जताते हुए अनुपस्थितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दूसरे सत्र में मंच साझा करने से पहले ही अग्रवाल कार्यशाला छोड़कर निकल गए। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म उन्हें मनाने भी पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने। बाद में डॉ. अग्रवाल ने कहा कि उन्हें भाजपा नेताओं श्रवण बगड़ी और गजेन्द्र सिंह खींवसर से पूर्व निर्धारित मुलाकात के लिए निकलना था। उन्होंने कहा कि

- **सूत्रों के अनुसार, कार्यशाला में केवल 5 सांसद, 72 विधायक, 42 प्रत्याशी और 13 जिलाध्यक्ष ही पहुंचे थे। प्रभारी अग्रवाल ने अनुपस्थितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी दी।**

''मंत्री बेढ़म ने रुकने का आग्रह किया, लेकिन तय कार्यक्रम के चलते मुझे जाना पड़ा।'

कार्यशाला में मुख्यमंत्री शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, केन्द्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद दामोदर अग्रवाल, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल, पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित रहे। कार्यशाला के अंत में युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित चेची द्वारा युवा मैराथन के पोस्टर व टी-शर्ट का विमोचन किया गया। मंच संचालन कुलदीप धनकड़ व मुकेश दाधीच ने किया। सेवा पखवाड़ा अभियान के संयोजक संतोष अहलावत ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी।

ट्रम्प के प्रबल समर्थक, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रपति बंदूकधारियों द्वारा मारे जा चुके हैं। लेकिन कटुता और नफरत इस स्तर पर पहले कभी नहीं देखी गई, जैसी डॉनल्ड ट्रंप के समय में दिख रही है।

ट्रंप ने अमेरिकी संस्थाओं को चुनौती दी और चुनाव परिणाम को ठुकराते हुए राजधानी में अराजकता फैलाई। उन्होंने अपने समर्थकों को वॉशिंगटन बुलाया, जिन्होंने बाद में कैपिटल हिल पर धावा बोला। इसमें कुछ सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई और कई घायल हुए और कई गिरफ्तार किए गए। हिंसा और सरकारी संस्थाओं पर हमले की निंदा करने के बजाय ट्रंप ने डेमोक्रेट्स और चुनाव व्यवस्था पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 2016 में उनका चुनाव ''चुरा'' लिया, जब जो बाइडन विजेता घोषित किए गए।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति में एक अलग तरह का वैमनस्य भर दिया। इससे पहले तक

- **ट्रंप का नारा ''मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'' और इस दर्शन के अंतर्गत चलाए गए अभियान ने अमेरिका के समाज में गहरी खाइयां बना दी हैं, जिसकी कीमत अब अमेरिका चुका रहा है।**

वहां राजनीति में विचारों और मुद्दों पर मतभेद होते थे, लेकिन निजी जीवन में राजनीतिक विरोधी भी आपस में दोस्त बने रहते थे। ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति की इस परंपरा को बदल डाला।

ट्रंप ने अपनी राष्ट्रपति पद की दौड़ 2015 में शुरू की थी, जिसमें उन्होंने प्रवासियों और मैक्सिकन नागरिकों पर ज़हरीले हमले किए और आरोप लगाया कि ये लोग हिंसा, अपराध और अन्य बुराइयां फैला रहे हैं। लेकिन मुख्यधारा की राजनीति ने इस तरह की बयानबाज़ी पर कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे-धीरे पूरी रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के आगे झुक गई और उन्हें नफरत और टकराव भरे भाषणों की पूरी छूट दे दी। इसी बीच, अश्वेतों की पुलिस के हाथों मौत पर देशभर में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। ऐसी घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला पूरे अमेरिका में देखने को मिली। बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद, जो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ट्रंप ने अश्वेतों के प्रति नफरत को और हवा दी। उसके बाद से यह लहर और भी तेज़ होती गई। लेकिन अब आम अमेरिकी नागरिक घटनाओं की इस दिशा को लेकर गहराई से चिंतित हो रहे हैं। लोग अमेरिकी राष्ट्रपति की हरकतों को नकारात्मक रूप से देखने लगे हैं और हाल ही में उनकी लोकप्रियता तेजी से गिर गई है।

भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल होने के झांसे में नहीं आयें

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। रूस की सेना में कुछ भारतीय नागरिकों की भर्ती की मीडिया रिपोर्टों के बीच, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को आगाह किया है कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव के

- **विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को इसके खतरों से फिर आगाह किया।**

झांसे में न आए, क्योंकि इसमें कई जोखिम हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती से संबंधित मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि, हमने हाल ही में रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती की खबरें देखी हैं। सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों पर इस तरह की कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और तदनुसार भारतीय नागरिकों को आगाह किया है।

उन्होंने कहा कि भारत ने मास्को और यहां, दोनों जगहों पर रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और अनुरोध किया है कि इस प्रथा को समाप्त कर हमारे नागरिकों को वापस भेजा जाना चाहिए।

ब्लूटूथ से नकल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से नकल कर चयनित हुए थे। फिलहाल एसओजी की टीम उनसे पूछताछ करने में जुटी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित हुए कनिष्ठ लिपिक राम प्रकाश जाट निवासी कुचेरा जिला नागौर और सुनील विश्नोई निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।

सिंह ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से कनिष्ठ न्यायिक, सहायक लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती के संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 12 मार्च 2023 एवं 19 मार्च 2023 को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई थी, जिसमें आरोपी राम प्रकाश जाट का परीक्षा केन्द्र विजयन डी. सूरी जैन विद्यापीठ सी. सै. स्कूल, नागौर (राजस्थान) था और आरोपी सुनील विश्नोई का परीक्षा केन्द्र श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन सी. सै. स्कूल हनुमानगढ़ (राजस्थान) था। संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपी पौरव कालेर निवासी छापर जिला चूरू द्वारा सालासर से मोबाइल फोन के माध्यम से राम प्रकाश जाट और सुनील विश्नोई को ब्ल्यूटूथ डिवाइस से नकल करवाई थी।

इसके लिए 4 लाख रूपये में सौदा तय हुआ था। आरोपी राम प्रकाश जाट नकल कर पास हो गया था और वर्तमान में पॉक्सो कोर्ट कम संख्या-01 उदयपुर में पदस्थापित था तथा विगत 7 माह से फरार चल रहा था। सुनील विश्नोई जिला सैशन कोर्ट हनुमानगढ़ में पदस्थापित था तथा गिरफ्तारी के भय से गत 6 माह से स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित था एवं फरार चल रहा था।

महिला एईएन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने के एवज में अलग-अलग तरीके से रिश्वत की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 35 से 40 लाख रुपए का ठेकेदार का बिल था।

गत एक साल से ठेकेदार को परेशान किया जा रहा था। ठेकेदार की शिकायत मिलने के बाद मामले का गुप्त तरीके से भौतिक सत्यापन कराया गया। भौतिक सत्यापन में मामला सही पाए जाने के बाद गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापा मारकर पांच कर्मचारियों को 3 लाख 10 की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। आयुक्त से भी पूछताछ की जा रही है।

भौतिक सत्यापन में आयुक्त अशोक शर्मा के नाम का भी जिक्र हुआ है। फिलहाल धौलपुर में अचानक की गई एसीबी की कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद नगर परिषद कार्यालय का पूरा दफ्तर खाली हो गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। अनुसंधान के बाद आरोपियों को भरतपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

तीन हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। उच्चतम न्यायालय कोलीजियम ने उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को पदोन्नत कर मुख्य

- **न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय, एम. सुंदर को मणिपुर तथा बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जायेगा।**

न्यायाधीश बनाने की गुरुवार को सिफारिश की। शीर्ष अदालत की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गयी है। इसी प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी को उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गयी है।

राजस्थान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कौशल विकास में संगठन की भूमिका की सराहना की, जबकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने तकनीकी शिक्षा में हुई प्रगति को साझा किया।

आइडियोथॉन में जयपुर के तन्मय व्यास और चारू वैष्णव के स्टार्टअप को प्रथम पुरस्कार मिला। रेल मंत्री ने इनके -बनाए ट्रेन स्पीड कंट्रोल प्रोटोटाइप को रेलवे में परीक्षण करने का निर्देश भी दिया। कार्यक्रम में स्टोनमार्ट-2026 के ब्रोशर का विमोचन भी हुआ। इस मौके पर लघु उद्योग भारती प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, महेंद्र खुराना, नरेश पारीक, नटवरलाल अजमेरा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

केदारनाथ, 2500 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक लाख रुपये खर्च हो चुके थे। डेढ़ सौ रुपये में पानी की बोतल, 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जबरन कराए गए पूजा-पाठ, और मंदिर स्टाफ द्वारा चलाए जा रहे आवास घोटालों ने पूरी तस्वीर को और भी गंभीर बना दिया।

ऐसी ही कहानियाँ बैद्यनाथ, हरिद्वार और द्वारका जैसे अन्य पवित्र स्थलों से भी सामने आ रही हैं, जहां दलाल, बिकाऊ कतारें और जर्जर बुनियादी ढांचा श्रद्धालुओं की आस्था की अग्निपरीक्षा ले रहे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों की गरिमा छीनी जा रही है... और क्यों वैश्विक मानकों पर आधारित एक ''टैंपल चार्टर'' ही इसका स्थायी समाधान हो सकता है।

एसआई भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसआई को स्वतंत्र निर्णय और काम करने की छूट दी जाती है।

इसके अलावा, एकलपीठ ने जिन रिपोर्ट्स के आधार पर भर्ती को रद्द करने योग्य माना था, खंडपीठ ने उन रिपोर्ट्स को अप्रमाणित मान लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट राफेल केस में तय कर चुका है कि दस्तावेज किसी भी माध्यम से मिला हो, यदि वह सही है तो कोर्ट उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता।

वहीं, यदि दागियों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कम होगा। दूसरी ओर खंडपीठ के अपीलार्थी अमर सिंह व विक्रम पंवार की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पेश कीगई है।

मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक भाजपा का सेवा पखवाड़ा

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती दो अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनायेगी।

इस अभियान में सेवा, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रनिर्माण को केन्द्र में रखा गया है। इसके अंतर्गत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैम्प, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण के लिए ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान, प्रदर्शनी, संवाद कार्यक्रम, दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण, ''मोदी विकास

- **सेवा पखवाड़े में मोदी के जीवन व उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जायेंगी।**

मैराथन'', खेल महोत्सव और ड्राइंग प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेन्द्र यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद और सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के साथ-साथ 771 संवाद कार्यक्रम भी देशभर के सभी प्रांतों में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का 17 सितंबर को जन्मदिवस है और उन्होंने भारत की राजनीति में सेवा, स्वच्छता जैसे मौलिक विषयों को सबके सामने स्थापित किया है।

'मोदी कार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1500 सीसी डीजल) पर कर घटाकर, 18 प्रतिशत (पहले 29-31प्रतिशत) कर दिया है, जबकि बड़ी कारों (4 मीटर से अधिक, 1500 सीसी से ऊपर की इंजन क्षमता और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस) पर कर घटाकर, 40 प्रतिशत (पहले 50 प्रतिशत) किया गया है। इसके साथ ही, केन्द्र सरकार ने मुआवजा उपकर (कैम्पन्सैशन सैस) भी हटा लिया है। पूर्व पत्रकार और मीडिया प्रोफेसर प्रदीप माथुर ने टिप्पणी की, ''ऐसी कवायद को आमतौर पर अनैतिक श्रेणी में रखा जाता, लेकिन वर्तमान सरकार इसे अपने विशेषाधिकार के रूप में देखती है।''

मोदी के लेख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर उनके लिए लिखा गया ''हद से ज़्यादा स्तुतिपरक लेख'' संघ नेतृत्व को रिझाने की ''हताशा भरी कोशिश'' है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भागवत की बौद्धिक गहराई और परोपकार से भरे नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2009 से आरएसएस प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल संगठन की 100 साल की यात्रा का सबसे परिवर्तनकारी दौर माना जाएगा। गुरुवार (11 सितंबर 2025) को कई अखबारों में प्रकाशित एक प्रशंसात्मक लेख में, मोदी ने कहा कि भागवत 'वसुधैव कुटुंबकम' के जीवंत उदाहरण हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन और सद्भाव व भाईचारे की भावना को सशक्त करने के लिए समर्पित किया है कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व की कृपा पाने की व्यग्रता में मोहन भागवत के 75 वें जन्मदिन पर हद से ज़्यादा स्तुतिपरक लेख लिखा है।''रमेश ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने यह याद दिलाया है कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना अमर भाषण दिया था। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि 11 सितंबर 2001 को ही अमेरिका में अल कायदा के आतंकवादी हमले हुए थे।'' कांग्रेस नेता ने 'एक्स' पर आगे लिखा, ''लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री ने यह उल्लेख नहीं किया कि महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में पहली बार सत्याग्रह का आ ान किया था। उसी दिन दुनिया ने पहली बार इस क्रांतिकारी विचार को सुना था।'' रमेश ने कहा, ''बेशक, यह उम्मीद करना बहुत ज़्यादा होगा कि प्रधानमंत्री सत्याग्रह की उत्पत्ति को याद रखें, क्योंकि उनके लिए तो सत्य शब्द ही पराया है।''उन्होने कहा, ''प्रधानमंत्री, जो खुद को ''नॉन बायोलॉजिकल'' बताते हैं, अपने प्रवचनों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, जैसे वे ईश्वरीय कथन हों।''

राष्ट्रपति व राज्यपाल की विधेयक मंजूरी की समय सीमा पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर 10 दिन संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंज़ूरी देने की समय-सीमा निर्धारित करने के विवाद से जुड़े राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की संविधान पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें 10 दिनों तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

राष्ट्रपति संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंज़ूरी देने की समय-सीमा से संबंधित प्रश्न उठाए गए थे।

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह संदर्भ प्रस्तुत किया गया था, जो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख को किसी भी कानूनी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।

राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में 14 प्रश्नों पर शीर्ष अदालत की राय मांगी। सवालों में यह भी शामिल है कि क्या देश के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायोचित है। संदर्भ में राय मांगी गई है, ''क्या संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के

- **राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे रैफरेन्स में शीर्ष न्यायालय से 14 प्रश्नों पर राय मांगी थी।**

निर्णय, कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले, किसी भी रूप में, उसकी विषय-वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना अनुमन्य है?''

राष्ट्रपति की ओर से यह भी राय मांगी गयी है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी लागू कानून है।

इसमें यह भी राय देने को कहा गया है, ''क्या संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वाद के माध्यम से छोड़कर, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए शीर्ष न्यायालय के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है?'' राष्ट्रपति ने महसूस किया कि मौजूदा परिस्थितियों में जब राज्य सरकारें अक्सर संविधान के अनुच्छेद 32 और 131 का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं, कानूनी प्रश्नों पर शीर्ष अदालत की राय लेना समय की मांग है।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति संदर्भ के मामले में 22 जुलाई को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर इन सवालों पर अपना पक्ष रखने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को कहा था कि वह 29 अगस्त से 10 सितंबर के दौरान सुनवाई संबंधित पक्षों की दलीलें सुनेगी।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ (शीर्ष अदालत में) ने आठ अप्रैल, 2025 के अपने एक फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा 10 विधेयकों को पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के फैसले को अवैध घोषित किया था।

छत्तीसगढ़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली ढेर

गरियाबंद, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को गुरुवार को तब बड़ी सफलता मिली, जब सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी नक्सली समेत दस नक्सलियों को मार गिराया।

आज सुबह थाना मैनपुर क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की सक्रियता की सूचना मिलने के बाद ई 30, विशेष सुरक्षा बल और कोबरा की संयुक्त टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लंबी और तीव्र मुठभेड़ हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ में माओवादी केन्द्रीय कमेटी के कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। माना जा रहा है कि इनमें एक प्रमुख नक्सली मनोज भी शामिल हैं, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। राखेचा ने बताया कि अभियान पूरी तरह से सुरक्षा बलों की रणनीति के तहत संपन्न हुआ।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908